

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शारान।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 13 जनवरी, 2009

विषय-एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड को तहसील विकास नगर के ग्राम झाझरा में सम्पर्क मार्ग हेतु भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड को शारानादेश संख्या-794/18(1)/2008 दिनांक-21 अगस्त, 2008 के द्वारा तहसील विकासनगर परगना पछवाडून के ग्राम ईस्ट डोप टाउन तथा ग्राम झाझरा में कुल 6 है० पट्टे पर आवंटित भूमि पर सम्पर्क मार्ग हेतु आपके कार्यालय के प्रस्ताव/पत्र संख्या-79/12ए-09(2008-2011) डी०एल०आर०सी० दिनांक-11 नवम्बर, 2008 के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-258/18(1)/73-रा-1 दिनांक-09 मई, 1984 एवं यथाराशोधित शारानादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-रा-1 दिनांक-12.09.1997 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार तहसील विकासनगर, जिला देहरादून के ग्राम झाझरा के खसरा नं०-1166मि० रकबा 0.4580 है० भूमि वर्तमान बाजार दर की दो गुने से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एकागुस्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के बीस गुने के बराबर वार्षिक किसानों नियत कर एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, नई दिल्ली को उक्त वर्णित पूर्व में पट्टे पर आवंटित भूमि पर सम्पर्क मार्ग बनाये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहमति स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
- (2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा०-6 दिनांक-09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रांट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्षों के लिए इस नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

- (4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता भट्टेदार को न रह जायेगी, तो भूमि निर्माण(Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय नहीं होगा।
 - (5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, अथवा आर्गनाइजेशन(संस्था) का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
 - (6) भूमि आवंटन से पूर्व नियमानुसार श्रेणी परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।
 - (7) भूमि पर सम्पर्क मार्ग बनाये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी/विभाग की अनापत्ति(अनापत्तियाँ) प्राप्त कर ली जायेगी।
 - (8) आवंटित भूमि का प्रयोग संस्था को पूर्व में आवंटित भूमि पर सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के लिए ही किया जायेगा।
 - (9) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-1 से 8 तक की विनयी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- 2- उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

69

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन सं०- (1)/तददिनांक/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2-सचिव सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3-आयुक्त गढ़वाल गण्डल, पीडी।
- 4-श्री ए०एम० बहुगुणा, डिप्टी कमिश्नर(अ०प्रा०), निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड, अजली गिहार, अजनपुर कला, देहरादून।
- 5-डायरेक्टर जनरल, एयरफोर्स गेवल हाउसिंग बोर्ड, एयरफोर्स स्टेशन, नई दिल्ली-110003
- 6-मेजर जनरल श्री मोहन सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन, साउथ इंटिमेंट, कश्मीर हाउस, राजा मार्ग नई दिल्ली।
- 7-निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 8-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रान्तोष बड़ानी)
अनुसचिव।